4. De-licensing of schemes for exploitation of alternate sources of energy.

5. Special attention to the development of industries in "No Industry Districts" and notified backward areas.

6. Creation of a special cell in the Secretariat for Industrial Approvals Department of Industrial Development) to receive and process industrial investment and licence applications from non-resident Indians.

7. Review of investment policies in order to provide a positive production orientation to the industrial economy is a continuous exercise.

The Union Budget for 1983-84 contains certain proposals aimed to encourage higher production.

Settlers in Andaman & Nicobar Islands

2980. SHRI MOHAMMED ASRAR AHMAD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that people from the mainland who settled in the Andaman and Nicobar Islands are subject to certain disabilities and different treatment;

(b) whether they are also facing a hostile attitude from the Islanders; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Production of Uranium

2981. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of plants working in India for the production of uranium;

(b) whether their production is enough for the needs of the atomic power plants in the country; and

(c) plants under way to increase the production of uranium?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Uranium Corporation of India Limited (UCIL), a Public sector Undertaking, operates a Mine & mill at Jaduguda, Singhbhum Distt., Bihar, for production of Uranium Concentrates. They have also set up a Uranium Recovery Plant at Rakha, nearby, to treat the copper tailings from M|s. Hindustan Copper Limited (HCL), for recovering uranium.

(b) and (c). The production UCIL is adequate to meet the needs of the existing atomic power plants of the country. In order to meet the future additional requirements, UCIL has started work on a new uranium mine, and proposes to take up three more uranium mines during the current Five Year Plan.

छठी योजना में राजस्थान में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये आवंटन

2982. श्री मूल चन्द डागा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के मुख्य रूप से जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कुल और वर्षवार धन का कितना आंवटन किया गया है और वर्ष 1980–81 और 1981–82 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है है कि राजस्थान के किन जनजाति क्षेत्रों में इस धन का उपयोग किया गया; और

(ग) पाली क्षेत्र (राजस्थान) के लिए अब तक कुल कितना धन आवंटित

किया गया है और कितने धन का उपयोग किया किया गया है और क्षेत्रवार कितने आदिवासी परिवारों को निधनता रेखा से ऊपर लाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राजस्थान में जनजातियों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल वर्षवार-आवंटित धनराशि इस प्रकार से है :-

	राज्य योजना एस० सी० ए० और अन्य (रुपए लाखों में)
1980-85	25590.20
1980-81	4240.81
1981-82	5130.36

(ख) राज्य सरकार को सूचना के अनुसार इन धन राशियों का प्रयोग बांसवाड़ा और डुंगर पुर जिलों उदयपुर चित्तोड़ गढ़ और सिरोही जिलों की तहसीलों में और राजस्थान के विभिन्न जिलों में 36 क्षेत्र में किया गया ।

(ग) 1978-83 के दौरान पाली क्षेत्र के लिए 21.01 लाख ० आवंटित किए गए । राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 1981-82 तक 16 लाख रु० का उपयोग किया गया है जिससे 386 जनजाति परिवारों को लाभ हुआ ।

छठी पंचवर्षीय योजना में पूंजी निवेश

2983. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 97,500 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां तो अब तक कितनी धन राशि लगाई गई है और छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) जी, हां । छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 1979-80 की कीमतों पर 97,500 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

(ख) छठी पंचवर्षीयज योजना के पहले चार वर्षों में सरकारी क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना परिव्यय की कुल राशि 79103.31 करोड़ रु० है जो नीचे दी गई है :--

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु०)
1980-81	15109.03
1981-82	17417.31
1982-83	21081.65
1983-84	25495.32 (असम के लिए अनंतिम योजना परिव्यय शामिल है)
	79103.31

प्रधान वस्तुओं के उत्पादन तथा तथा सेवाओं के छठी योजना के लक्ष्यों के ब्यौरे छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के पृष्ठ 39 पर दिए गए हैं जिसे 6 मई, 1981 को सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था ।